ज्ञानी बजट को बताया विकसित मध्यप्रदेश व सर्वांगीण विकास का रोडमैप

इंदौर. बुधवार को उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए बजट को जनप्रतिनिधियों और उद्योगपतियों ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोडमेप बताया. वहीं महिलाओं व युवाओं ने इसे संतुलित बजट बताया. फसलों के समर्थन मूल्य पर कोई पहल ने होने से किसानों में हताशा है.

शहरी विकास पर पूरा फोकस

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि गरीब, युवा अन्नदाता और नारी कल्याण के लिए समर्पित बजट बनाया है. साथ ही बजट में एग्रीकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट के साथ साथ शहरी विकास पर पूरा फोकस किया गया है. उन्होंने कहा कि बजट में नगरीय विकास में मूलभूत सुविधाओं के लिए 1 हजार 57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे नगरों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, परियोजनाओं को गति मिलेगी. आधुनिक तकनीक, हरित ऊर्जा और लोक परिवहनों और सुरक्षा के नए घटकों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मप्र के शहर विकास के नये आयाम रच रहे हैं. इसके अतिरिक्त गांव, गरीब, किसान, महिला, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, विमुक्त जाति, जनजाति, धर्म, अध्यात्म, सिंहस्थ, पर्यटन, औद्योगिक अर्थात सबका साथ- सबका विकास- सबका कल्याण के मूलमंत्र के साथ बजट तैयार किया गया है.

सर्वांगीण विकास का रोडमैप

भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि बजट में प्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोडमैप दिखाई देता है. मुख्यमंत्री डॉ यादव के नेतृत्व में बजट में ग्यान- गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ इंडस्ट्रीयलाईजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ा है, जो इस अमृतकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की संकल्पना में प्रदेश की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा. रोलिंग बजट में आगामी 3 वर्षों की कार्ययोजना का खाका प्रस्तुत किया गया है, यह रोलिंग बजट देश के अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बनेगा. किसानों के लिए बजट में 3 हजार करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर सिंचाई पम्प, नेचुरल फार्मिंग, अल्प कालीन कृषि ऋण, कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए 88 हजार 910 करोड़ के प्रावधानों से अन्नदाता को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जाएगा. साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विभिन्न सेक्टर मेट्रो ट्रेन, ऊर्जा, सड़क, ब्रिज, हर घर जल, सिंचाई आदि क्षेत्रों में प्रावधान कर हर वर्ग की चिंता की. वास्तव में यह बजट मध्य-प्रदेश 2047 विकसित प्रदेश की ओर ले जाएगा.

विकसित मप्र बनाने का दृष्टि पत्र

विधायक रमेश मेंदोला ने बजट को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बताते हुए कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओ के कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं. सिंहस्थ, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन और संस्कृति के लिए प्रावधान किया गया है, जो सर्वजन हिताय- सर्वजन सुखाय के मूलमंत्र के साथ विकसित मध्य-प्रदेश बनाने का दृष्टि पत्र है.

ज्ञान की सोच के अनुरूप बजट

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ मध्य प्रदेश विकास की नई उड़ान भर रहा है. आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट आत्मनिर्भर एवं विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प का मजबूत आधार है. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्यान की सोच के अनुरूप यह बजट गरीब, युवा, किसान और मातृशक्ति को सशक्त करने की दिशा में ठोस कदम है. प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. किसानों के सशक्तिकरण के लिए पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी. लाड़ली बहनों को सशक्त बनाने का अभियान जारी रहेगा. शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है.

युवाओं पर विशेष फोकस

विधायक गोलू शुक्ला ने कहा कि मध्य-प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में मिल का पत्थर साबित होगा बजट, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत- विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है. बजट में युवाओं पर विशेष फोकस किया गया है, खेल, 2 आई (इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीयलाईजेशन) के माध्यम से युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने का प्रावधान किया गया है.

नारी सशक्तिकरण के विशेष प्रावधान

विधायक मालिनी गौड ने कहा कि बजट में नारी सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. समाज में भ्रम फैलाया जा रहा था कि लाडली बहना योजना बंद कर देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली महिला हितैषी सरकार ने 23882 करोड़ रुपये का प्रावधान कर भ्रमित करने वाले को जवाब दिया है. साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना, यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना से 8 वीं कक्षा तक के बच्चों का स्वास्थ्य मजबूत बनेगा. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल निर्माण के प्रावधान से कामकाजी महिलाओं का बोझ कम होगा.

हर वर्ग के कल्याण को दी जगह

विधायक महेंद्र हार्डिया ने कहा कि बजट में हर वर्ग हर तबके के कल्याण को जगह दी गई है। साथ ही कृषि, अधोसंरचना विकास, ऊर्जा, औद्योगिकीकरण के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रावधान किए हैं. आयुष्मान योजना के लिए 2139 करोड़ रुपये के साथ 8 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी, इससे हमारी प्राचीन आयुर्वेद शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी. स्वास्थ्य क्षेत्र में 23747 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं, जिससे प्रदेश में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी.

ग्रामीण विकास पर भी पूरा ध्यान

विधायक मधु वर्मा ने कहा कि बजट में शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया है. बजट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 40062 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी समग्र विकास सम्भव होगा. गांवों में सड़कों के उन्नयन, संधारण के साथ साथ 4 लाख प्रधानमंत्री आवास का निर्माण, जी राम जी विकसित भारत योजना के लिए 10,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिक वर्ग को बेहतर रोजगार उपलब्ध होगा.

जीवन स्तर सुधारने का रोड मैप

भाजपा के सह मीडिया प्रदेश प्रभारी दीपक जैन टीनू ने कहा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जनकल्याण, सामाजिक न्याय और सर्वहारा वर्ग के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक है. यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला और श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने का ठोस रोडमैप है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनहितैषी संकल्पों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी ने किसानों के लिए 3000 करोड़ रुपये खर्च कर 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का निर्णय प्रदेश के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. भाजपा सरकार का यह बजट सर्वहारा वर्ग, किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं और उद्योग के माध्यम से आमजन के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने वाला साबित होगा. यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प को जमीनी स्तर पर लागू करने का मजबूत प्रयास है. जनहित, ग्रामीण उत्थान, उद्योग और सर्वहारा सशक्तिकरण का बजट, मोहन यादव सरकार ने विकास का नया रोडमैप दिया.

मांग सशक्तिकरण से विकास की संभावनाएं

सीए मोहित शर्मा ने कहा कि लाड़ली बहना योजना, किसान कल्याण योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा हुआ खर्च राज्य में मांग को मजबूत करेगा। यदि राजस्व संग्रह लक्ष्य के अनुसार रहा तो यह बजट विकास और सामाजिक संतुलन का अच्छा उदाहरण बन सकता है. निवेश और रोजगार सृजन पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है.

बुनियादी ढांचे में निवेश से व्यापार को नई गति

व्यवसायी तरुण शर्मा ने कहा कि बजट में उद्योग और बुनियादी ढांचे पर जोर स्वागतयोग्य है. सड़कों और कनेक्टिविटी में सुधार से व्यापार को सीधा लाभ मिलेगा. अगर सरकार योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करे तो राज्य में निवेश और कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे.

उद्योगपतियों ने कहा...

औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना उद्योग हितैशी

एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मप्र के अध्यक्ष योगेश मेहता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वित्तमंत्री द्वारा पेश किये बजट को सर्वस्पर्शी बजट निरूपित करते हुए बजट का स्वागत किया है. आपने प्रदेश में औद्योगिक निवेश हेतु अनुकुल वातावरण व 48 नये औद्योगिक पार्को का विकास के लिए 5957 करोड रू के प्रावधान को औद्योगिककरण की दिशा में सकारात्मक पहल बताया है. बिजली क्षमता बढाने पर जोर देने, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, नारीशक्ति, सशक्त और आत्मनिर्भर महिला व युवा शक्ति को बढावा देने के लिए कौशल विकास व रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणाओं आदि पर फोकस राज्य को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की योजना है जो उद्योग हितैशी है.

प्रदेश के विकास में हितैषी बजट

एसोसिएशन के सचिव तरूण व्यास ने राज्य सरकार द्वारा कोई नया टैक्स नही लगाने और टैक्स नहीं बढाने के ऐलान का स्वागत करते हुए वित्त वर्ष 2026-27 में बजट में 11 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदेश के विकास हितैशी बताया है. आपने अधोसंरचना विकास के अन्तर्गत सडकों ओर पुलों के लिए 12 हजार करोड रू के प्रावधानों का स्वागत किया है.

सभी वर्गों का रखा ध्यान

एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने राज्य बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि बजट सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए पेश किया गया है जिसमें औद्योगिकरण और आधोसरंचना विकास पर ध्यान दिया गया है। युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता हर हाथ को काम और हर उपज को काम देने का प्रावधान स्वागतयोग्य है तथा मध्यप्रदेश का बजट विकसित भारत के सपने में योगदान देता प्रदर्शित हो रहा है.

जनता को समर्पित बजट

फार्मा सेक्टर एवं फार्मा एसोसिएशन के सचिव अजयसिंग दासुंदी ने राज्य बजट को जनता को समर्पित बजट बताया है. आपने कहा कि बजट में स्वास्थ सेवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है जो फार्मा उद्योगों को गति प्रदान करेगा. विकसित प्रदेश के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी बजट प्रदेश के फार्मा उद्योगों को नई दिशा प्रदान करेगा, निवेश व रोजगार के अवसरों के साथ अधोसंरचना को सुदृढ बनाने व जनकल्याणकारी योजनाओं आदि में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करेगा यह बजट.

महिला सशक्तिकरण और परिवारों को सीधी राहत की पहल

स्वाति शर्मा ने कहा कि इस बजट में महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वे सराहनीय हैं. लाड़ली बहना योजना से मिलने वाली सहायता घर के रोज़मर्रा के खर्चों में सहारा देती है. बच्चों को मुफ्त दूध देने जैसी पहल से उनके स्वास्थ्य की चिंता कम होगी. यदि योजनाओं का लाभ समय पर और नियमित रूप से मिले, तो यह सच में परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा.

बिना नए कर बोझ के विकास पर जोर

आर्किटेक्ट दीप्ति रुघानी ने कहा कि इस बजट का सकारात्मक पक्ष यह है कि सरकार ने बिना किसी नए कर बोझ के विकासोन्मुखी व्यय को प्राथमिकता दी है. लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपए के बजट में कृषि, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर बड़ा आवंटन किया गया है. राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय बढ़ाना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालीन रूप से लाभकारी रहेगा.

संतुलित विकास की ओर एक ठोस कदम

डॉ नेहा शर्मा ने कहा कि 4.38 लाख करोड़ रुपए का यह बजट सामाजिक सुरक्षा और पूंजीगत निवेश के बीच संतुलन स्थापित करता दिखता है. कृषि, महिला सशक्तिकरण और अधोसंरचना पर बढ़ा आवंटन सकारात्मक संकेत है. यदि राजस्व संग्रह लक्ष्य के अनुरूप रहा, तो यह बजट विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को मजबूती देगा.

कर्ज लो और घी पियो की तर्ज पर सरकार का बजट : रघु ठाकुर

मध्यप्रदेश सरकार का बजट प्रचारात्मक बजट है. यह उस ढोल के समान? है, जिसकी आवाज सुंदर लगती है परंतु ढोल भीतर से खोखला होता है. प्रदेश सरकार नए वर्ष में 54448 करोड़ का कर्ज ओर लेगी, जबकि, पहले से ही मध्य प्रदेश भारी कर्जदार है। बजट की बड़ी राशि कर्ज का ब्याज चुकानी पर जाएगी. समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने प्रदेश सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वास्थ के लिए 2500 करोड़ रुपए रखे गए हैं. उक्त राशि से प्रदेश में केवल 50000 लोगों को ही योजना के तहत उपचार मिलेगा, जो काफी कम है। छात्रवृत्ति, पेंशन, सामाजिक पेंशन आदि योजनाएं पूर्ववत हैं. कृषि और सिंचाई हेतु 44000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। क्या इतनी राशि से 20 लाख एकड़ जमीन को सिंचित किया जा सकेगा. सरकार ने दूध उत्पादन के लिए 2364 करोड़ रुपए प्रावधान किया है, परंतु यह दूध उत्पादन की वृद्धि किस रूप में होगी यह स्पष्ट नहीं है. 3000 गौशालाओं के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा है यह आधुनिकीकरण किस रूप में होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है. छात्रों को साइकिल योजना एक अच्छी योजना है और इसके लिए सरकार की मैं तारीफ करूंगा. 1 लाख सोलर पंप लगाने की योजना भी कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए. ठाकुर ने कहा कि आज से लगभग 35 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज मुक्त प्रदेश बनाने का वादा किया था, परंतु कर्ज निरंतर बढ़ रहा है. सरकार की वोट खरीदो योजनाओं पर जो खर्च किया जा रहा है, उसे चार्वाक के एक ही वाक्य में। ऋणम कृत्वा घृतम पियेत. इस बजट की सही व्याख्या यही है की कर्ज लो और घी पियो.

सामाजिक विस्तार के साथ राजकोषीय सतर्कता की आवश्यकता

वरिष्ठ अर्थशास्त्री और सीए सोमेंद्र शर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण मांग को स्पष्ट प्राथमिकता देता है। कृषि क्षेत्र के लिए 88,910 करोड़ तथा लाड़ली बहना योजना हेतु 23,882 करोड़ का प्रावधान आय-सहायता आधारित विकास रणनीति को मजबूत करता है। इससे अल्पकाल में ग्रामीण उपभोग, स्थानीय व्यापार और सूक्ष्म उद्योगों को गति मिलने की संभावना है. हालाँकि, राजकोषीय संकेतक सतर्कता की मांग करते हैं. अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के लगभग 3.5-3.7% के दायरे में है, जबकि ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात 28-30% के आसपास बना हुआ है. ब्याज भुगतान यदि राजस्व का 18-20% लेता है, तो भविष्य में पूंजीगत निवेश के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो सकते हैं. बजट की वास्तविक सफलता इस पर निर्भर करेगी कि पूंजीगत व्यय- विशेषकर अधोसंरचना, सिंचाई और उत्पादक क्षेत्रों में- कितनी दक्षता से लागू होता है। यदि राजस्व संग्रह सुदृढ़ रहा और ऋण प्रबंधन अनुशासित बना रहा, तो यह बजट सामाजिक प्रतिबद्धता और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है.

समर्थन मूल्य पर कोई ठोस पहल नहीं

भारतीय किसान एवं मजदूर सेना के अध्यक्ष बबलू जाधव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रावधानों की घोषणा की गई है, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी और जमीनी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया. प्रदेश के किसान लंबे समय से कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं. बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितता और बाजार में उचित दाम न मिलने के कारण किसान आर्थिक दबाव में हैं. ऐसे में बजट में कर्ज माफी की कोई ठोस घोषणा न होना किसानों के लिए निराशाजनक है. इसी तरह, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर भी कोई नई ठोस पहल या गारंटी का उल्लेख नहीं किया गया. किसान चाहते हैं कि गेहूं की खरीदी पूरी पारदर्शिता के साथ और समय पर हो, तथा एमएसपी पर कानूनी गारंटी सुनिश्चित की जाए. हालाँकि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए राशि आवंटन और योजनाओं का जिक्र किया गया है.

संभागायुक्त ने प्रशासनिक संकुल में किया औचक निरीक्षण

- कलेक्ट्रेट राजस्व न्यायालय में प्रकरणों को जांचा

नव भारत न्यूज

इंदौर. आज संभागायुक्त ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजस्व न्यायलयों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने लंबित प्रकरणों की जानकारी और प्रकरणों का जांच की. नामांकन, सीमांकन, बंटवारा प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की.

सम्भागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े आज प्रशासनिक संकुल में राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण करने पहुँचे. उन्होंने दो-तहसील, दो-अनुविभाग और दो-अपर कलेक्टर कोर्ट का रोस्टर निरीक्षण कर प्रकरणों के वस्तुस्थिति देखी. संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने दो-राजस्व तहसील न्यायालयों में बिचौली हप्सी व जूनी इंदौर अनुविभागीय राजस्व न्यायालयों का भी निरीक्षण किया. उनके साथ कलेक्टर शिवम वर्मा भी थे. निरीक्षण में डॉ. खाड़े ने नामांकन, सीमांकन, बंटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए है कि अधिकारी समय पर कार्यालय पहुँचे. सभी पक्षकारों के प्रकरणों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने पर विशेष ध्यान दे. साथ ही उन्होंने नामांकन, सीमांकन, बंटवारा प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने एवं राजस्व वसूली में भी गति लाने के निर्देश दिए.

अभियान का प्रभावी क्रियान्वन करें

संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने निर्देश दिए कि संकल्प से समाधान अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन करे. हर व्यक्ति को पात्रता के अनुसार शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिले. हितग्राहियों के चयन के लिए ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम और नगर परिषदों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. शिविरों में शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर और प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाए. लोकसेवा गारंटी योजना के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें. इस दौरान अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पंवार, रोशन राय, रिंकेश वैश्य, निशा डामोर और सभी एसडीएम व तहसीलदार मौजूद थे.

राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग, पॉवरलिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ

इंदौर. महाराजा रणजीत सिंह महाविद्यालय, इंदौर को म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की राज्य स्तरीय वेटलिफ्टिंग, पावरलिफ्टिंग (पुरुष/महिला) बॉडी बिल्डिंग (पुरुष) प्रतियोगिता का आयोजन का दायित्व सौंपा गया है। उक्त प्रतियोगिता महाविद्यालय के तत्वावधान में श्रीराम जिम्नेशियम रोबोट स्क्वायर के पास आयोजित की जा रही है. स्पर्धा का शुभारंभ सावन सोनकर, कैबिनेट मंत्री दर्जा, अध्यक्ष, म. प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित,

दिनेश पालीवाल सचिव मध्य प्रदेश वेट लिफ्टिंग एवं पावर लिफ्टिंग ऐसीशिएशन, सीबी होलकर इंदौर संभाग के वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी, विमल प्रजापत, राष्ट्रीय निर्णायक वेटलिफ्टिंग, दविंदर सिंह खनूजा राष्ट्रीय निर्णायक वेट लिफ्टिंग एवं पावर लिफ्टिंग, कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आनंद निघोजकर के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ. सभी अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी एवं स्पर्धा के अपर संगठन सचिव डॉ. निलेश मंडलोई, कॉलेज के क्रीड़ा समन्वयक डॉ. मितेश चौधरी, प्रो. प्रवीण शर्मा, डॉ. मनोज जोशी, डॉ. प्रदीप पूरे, डॉ. लाल कुमार, डॉ. शिफा गोयल, डॉ.दीप्ति बड़जातिया, डॉ. दीपक शर्मा के द्वारा किया गया. स्पर्धा के प्रथम दिवस में वेट लिफ्टिंग (महिला/पुरुष) एवं बॉडी बिल्डिंग (पुरुष) प्रतियोगिता आयोजित की गई. निर्णायक के रूप में संजय कराडे, जितेंद्र स्वामी, मनीष लश्करी, आदित्य जोशी, नरेन्द्र पाटीदार, दिलीप वर्मा, श्री संजीव राजदान, मीरा राजदान, रेखा अग्रवाल के द्वारा किया गया। क्रीड़ा अधिकारी डॉ. निलेश मंडलोई ने बताया कि इस स्पर्धा में मध्य प्रदेश के 9 परंपरागत विश्वविद्यालय भाग ले रहे हैं, जिसमें लगभग 110 खिलाड़ियों की प्रविष्टि प्राप्त हुई है. स्पर्धा का संचालन महाविद्यालय की प्राध्यापक डॉ. गीता सुरी के द्वारा किया गया एवं आभार डॉ. पुष्पेंद्र दुबे के द्वारा माना गया. इस स्पर्धा की आयोजन शासन से प्राप्त उच्च शिक्षा की खेलकूद मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है.

सरकार के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन

इंदौर. मोहन सरकार अब अंग्रेजों के जमाने को याद दिला रही है. आज किसान की हालत यह है कि उनकी निजी जमीनें बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बेची जा रही हैं. इसी के चलते अब किसान आरपार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं. बरलाई शुगर मिल से जुड़ी किसानों की भूमि के मुद्दे को लेकर बुधवार को सांवेर एसडीएम कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा.

प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व प्रदेश सचिव विजय राठौर 'बंटी' भैया ने किया. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान, शेयर धारक सदस्य और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे. धरने को संबोधित करते हुए विजय राठौर ने आरोप लगाया कि मालवा सहकारी शकर कारखाने की करीब 30.133 हेक्टेयर भूमि, जिसमें किसानों ने लगभग 50 वर्ष पूर्व शेयर लिए थे, उसे गुजरात क्रअडानी ग्रुप को दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है. राठौर ने कहा कि यह भूमि मूलतः किसानों से शकर मिल स्थापित करने के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई थी और उस समय किसानों से 500 से 1000 रुपए प्रति बीघा के भाव पर जमीन ली गई थी. साथ ही किसानों से 200 से 1000 रुपए लेकर उन्हें मिल के शेयर दिए गए थे. उन्होंने मांग की कि भूमि का नामांतरण तत्काल रोका जाए और जब तक किसानों का निर्णय न हो, शुगर मिल परिसर में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए. अंत में प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम घनश्याम धनगर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र राठौर, जनपद सदस्य पवन पटवारी, मोहन मुकाती, शंकर परमार, जनपद उपाध्यक्ष सुभाष चौधरी, प्रदीप दरबार, कृपाराम नेताजी, श्याम सोनी, सूर्य कुमार ओस्तवाल, उत्तम ठाकुर सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे.

एक नजर में — सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा संपन्न, हवन-यज्ञ व सेवा कार्य संपन्न

भक्ति मार्ग से जुड़कर सत्कर्म करना आवश्यक

इंदौर. दिव्य शक्तिपीठ परिसर, रेडिसन चौराहे के समीप आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का सर्वकल्याण की कामना के साथ समापन हुआ. कथा के समापन अवसर पर विधिवत हवन-यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया.

संत मदनमोहन दास महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि आत्मा को जन्म-मृत्यु के बंधन से मुक्त करने हेतु भक्ति मार्ग से जुड़कर सत्कर्म करना आवश्यक है. हवन-यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति को आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है. इस अवसर पर डॉ. निशांत खरे ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली आध्यात्मिक चेतना है.

भागवत कथा मनुष्य को सत्य, धर्म, सेवा, सदाचार और मानवता के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है. ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा, संस्कार एवं पारिवारिक एकता को सुदृढ़ करते हैं. कथा में महामंडलेश्वर रामगोपाल दास महाराज, उज्जैन के चरण दास महाराज एवं रामानंद आश्रम के मुनिदास महाराज ने भी उपस्थित रहकर भक्तजनों को आशीर्वाद प्रदान किया.

समापन पर संरक्षक डॉ. निशांत खरे एवं यजमान सूरज रघुवंशी ने व्यासपीठ पर आरती की. आयोजन के सातों दिनों में इंदौर के अनेक जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों ने उपस्थित होकर कथा का श्रवण किया. प्रमुख रूप से मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष श्रवण चावड़ा, विधायक गोलू शुक्ला, संजय शुक्ला, अभिषेक बबलू शर्मा, सौगत मिश्रा, दिव्या गुप्ता सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.